



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 16 मई, 2005/26 बैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 अप्रैल, 2005

संख्या पी० सी० १० एन०-एच० ए० (५) ७४/८१-८०५५-६१.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पंचायती राज विभाग को अपने/ग्राम पंचायत निविष्ट व्यय पर पंचायत घर पुजराली (ब्योलिया) तहसील शिमला (शामीण), जिना शिमला में भूमि अर्जित करना अपेक्षित है ;

अतः एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणों में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं/हो सकते हैं, की ज्ञानकारी के लिए भूमि अर्जन व्यविधियम, 1894 की धारा 4 (1) के उपबद्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त भूमि पर पंचायत घर पहले ही निर्मित है। इसलिए इस भूमि का अर्जन जनहित में अपरिहार्य है।

पूर्वकान्य धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यसंबंधी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव/स्थान	खसरा नं 0	क्षेत्र स्केयर यार्ड में
शिमला	शिमला (ग्रामीण)	मौजा कम्पुमटी-जुन्ना	201	75.40

आदेश

शिमला-171009, 30 अप्रैल, 2005

संख्या पीसीएच-एचए (5)-8296-8302--यह कि जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को सरकारी धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पंच-के 0 जी 0 आर-0-ई-1445-50, दिनांक 24-3-2004 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला के पद से निलम्बित किया गया था;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी, रैत, जिला कांगड़ा को उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पंच-के 0 जी 0 आर-0-ई-(15) 8/91-4747, दिनांक 13-9-2004 को जांच सौंपी गई थी;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्ज ए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाए गए उनका विवरण निम्न है:-

सं. 0.	निर्माण कार्य का नाम अथवा प्रयोजन	स्वीकृत राशि	प्रधान द्वारा प्राप्त राशि	निर्माण कार्य पर रिकार्ड अनुसार व्यय राशि	मूल्यांकन	दूरनियोजन कार्य की प्रगति	राशि अथवा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	निर्माण डंगा ताला ठाना राकेश भारती।	6000/-	4000/-	5,965/-	—	5,965/-	स्वीकृत योजना अनुसार भौका पर कार्य नहीं हुआ है।
2.	निर्माण प्रोटेक्शन पुली रास्ता ठाना राकेश भारती।	15000/-	10,000/-	14,869/-	—	14,869/-	पथ-1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	निर्माण रास्ता शिव मन्दिर से बलवंत सिंह के घर तक।	15,000/-	14,990/-	14,990/-	14,018/-	972/-	स्वीकृत योजना अनुसार मौका पर कार्य नहीं हुआ है।
4.	निर्माण रास्ता मुख्यमाना जस्तूर।	10,000/-	9,983/-	9,983/-	5,466/-	4,517/-	कार्य पूर्ण पाया गया।
5.	निर्माण रास्ता मुख्यहाल।	11,000/-	11,599/-	11,599/-	9,511/-	2,086/-	-प्रथा-
6.	निर्माण रास्ता कमनाला लोहार।	50,000/-	47,347/-	47,347/-	38,350/-	8,997/-	कार्य पूर्ण पाया गया।
7.	निर्माण रास्ता शिव मन्दिर से पीपलू टी।	25,000/-	24,948/-	24,948/-	22,949/-	1,999/-	स्वीकृत योजना अनुसार मौका पर कार्य नहीं हुआ है।
<hr/>							
1,33,000/- 1,22,867/- 1,29,701/- 90,294/- 39,407/-							

इसके अतिरिक्त शिव मन्दिर निर्माण कार्य हेतु खालान्त क्रय करते हुए कुल मु 12,164.65 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। इस प्रकार श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला द्वारा कुल मु 39,407 + 12,164.65 = 51,571.65 रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग तथा छलहरण किया गया है;

अतः यह कि, जाओ रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री जरम सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा बर्ती गई वित्तीय अनियमितताओं तथा मु 51,571.65 रुपये की राशि के दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यलय के समतंत्रक आदेश दिनांक 22-3-2005 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया;

अतः यह कि, श्री जरम सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, कमनाला, को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपत्तिक्रमक कार्यकलाप के फलस्वरूप दोषी पाए जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना उचित है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए श्री जरम सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा को उक्त कार्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा उक्त कार्य की कालागाड़ि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निवाचन के लिए निरहित किया जाता है।

शिल्पा-9, 4 मई, 2005

संख्या पी० सी० ए००८००५००१८४२१-२७.— यह कि उपायुक्त ऊना, जिला ऊना ने उनके कार्यालय पत संख्या पंच-ऊना (4)-13/89-1548-1552, दिनांक 31-12-2004 के अनुसार सूचित किया है कि श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा राजपूतां से वर्ष 1985 मे 1990 तक प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा राजपूतां के पद पर रहते हुए पंचायत समिति गगरेट में आमों की नीलामी से सम्बन्धित बकाया राशि कुल मु० 37,443/- रु० ब्याज सहित मु० 1,38,539/- रु० की राशि वसूली हेतु लम्बित है। उक्त राशि की वसूली हेतु श्री गिरधारी लाल को खण्ड विकास अधिकारी, गगरेट तथा उपायुक्त, ऊना द्वारा निरन्तर नोटिस जारी किये गए परतु फिर भी उक्त प्रधान द्वारा इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी आमों की नीलामी की बकाया वसूली राशि पंचायत समिति खाते में जमा नहीं करवाई। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2000 मे पुनः प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा के पद पर चुनाव हेतु मिथ्या घोषणा करके नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा राजपूतां के पद पर चुने गये।

यह कि श्री गिरधारी लाल, प्रधान द्वारा उपरोक्त वसूली राशि को पंचायत समिति खाते में जमा न करके तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (अ) व (इ) के अन्तर्गत आयोग्यता अंजित करने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत इस कार्यालय के समसंबद्धक आदेश दिनांक 22-२-२००५ के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि वे न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया।

अतः यह कि, श्री गिरधारी लाल द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथों पर अधिकारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा राजपूतां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (क) के अन्तर्गत आयोग्यता अंजित करने के फलस्वरूप उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुए श्री गिरधारी लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बडेडा राजपूतां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित तथा उस वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित करते हैं।

आदेश,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।